श्री नाथूराम मिर्धा : क्या पशुधन विकास के लिए और इस देश में दूध बढ़ाने के लिए इस कार्पोरेशन के चेयरमैन का दफ़्तर दिल्ली में होने से जनता को सुविधा होगी । क्या इस मामले पर सरकार गहराई से विचार करेगी कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी राज्यों की सुविधा इसमें है कि इस का हेडक्वार्टर दिल्ली में रखा जाए ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जब इस का हेडक्वार्टर शुरू में बनाया गया था 1970-71 में, उस वक्त एन० डी० डी० बी० का दफ़्तर क्योंकि आनन्द में था, इसलिए आई० डी० सी० का दफ़्तर नज़दीक रखना समझा गया और उसी वजह से इनका दफ़्तर बरौडा में बनाया गया । इसके अलावा नई दिल्ली में नये दफ़्तर लाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पापूलेशन यहां पर बहुत बढ़ी है और मिनिस्ट्री आफ़ वर्क्स एण्ड हाऊसिंग का यह फैसला हुआ है कि यहां पर नये दफ़्तर नहीं आने चाहिएं बल्कि यहां से दफ़्तर बाहर जाने चाहिएं । वहां से आपरेशन का काम ठीक होता रहा है, इसलिए उस दफ़्तर को यहां पर लाने का कोई विचार नहीं है ।

Consent of Rajasthan for Central Take-over of control of Regulator to Check Inter-State Floods

*407. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Rajasthan Government has conveyed its consent about the proposed take over by the Centre of the operational control of various regulators set up in the bordering regions of Haryana, U. P. and Rajasthan; and

(b) if so, the reaction of other States in this regard; and

(c) whether any permanent solution to the inter-State floods have been found and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As the existing capacity of the Goverdhan Drainage System is not adequate to discharge the flood waters in a reasonable period, the Central Water Commission was entrusted with the task of drawing up a feasible and acceptable scheme for remodelling the drainage system according to the best engineering practice in consultation with the engineers of the State Governments concerned. The Central Water Commission prepared a scheme for increasing the capacity of the drainage system, which was discussed with the State Government officers and its broad outline was finalised. A proposal was also drawn up for taking over of the operational control of certain key elements of the scheme by the Central Government. Rajasthan Government has accepted the proposal for operational control but has expressed reservations on the remodelling of the scheme itself. The other two States have also expressed their view points on the proposals made by the Central Government. A meeting was convened by the Union Minister for Agriculture and Irrigation, which was attended by the Ministers from Uttar Pradesh and Rajasthan and Chief Minister of Haryana to resolve the outstanding issues. The discussions were inconclusive.

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के बारे में इस हाऊस में बहुत विचार किया जा चुका है और जो जवाब मंत्री महोदय के स्टेटमेंट में है—मैं ने एक सीधा सा सवाल पूछा है कि राजस्थान सरकार की क्या इस बात में सहमति है कि रेग्युलेटरों का परिचालन नियंत्रण केन्द्र के हाथ में दिया जाए—उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन्स रखे हैं । उन्होंने यह कहा है :

Rajasthan Government has accepted the proposal for operational control but has expressed reservation on the re-modelling of scheme itself.

मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में गोवर्धन ड्रेनेज सिस्टम को री-माडल करने का जो काम हाथ में लिया गया है, इस को केन्द्र बना रहा है या राजस्थान सरकार कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह इन्टर-स्टेट फ्लड ड्रेन जो है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और यू० पी०, इन तीनों प्रान्तों में हो कर जाता है, उसके लिए जो रेग्युलेटर्स लगे हुए हैं, उसके बारे में जो पिछली मीटिंग हुई थी और

प्राइम मिनिस्टर साहब ने वह मीटिंग की थी, उस में ऐसा ख्याल था कि रेग्युलेटरों का काम सेन्टर के हाथ में होना चाहिए ताकि फ्लड को रेगूलेट किया जा सके और सारे एरिया के लिए जो स्कीम बनाई गई थी उस में अलग-अलग स्टेट्स को अपने हिसाब से कि कितना पानी उनके यहां इकट्ठा होता है, ड्रेन में पानी डालने के लिए नई स्कीमें बनानी थीं । हरियाणा ने अपनी नई ड्रेन बनाई और उसमें 500 क्यूसेक्स पानी जाने लगा है । परसों, चौथे उसका इन-आगुरेशन था । इसी तरह से यू० पी० ने भी नई स्कीम बनाई है । राजस्थान का यह ख्याल है कि 640 क्यूसेक्स पानी उनके यहां जाता है लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का कहना यह है कि उनको 1650 क्यूसेक्स का इन्तजाम करना चाहिए, जोकि उन्होंने नहीं किया है ।

श्री एस० एस० सोमानी : क्या मंत्री महोदय, को यह पता है कि अभी तक राजस्थान की नदियों पर तटबन्दी के लिए कोई काम नहीं किया गया है, जिसके कारण कई गांवों में मवेशी, आदमी और फ़सल का नुकसान होता है, तो क्या राजस्थान की नदियों के लिये तटबन्दी का काम वे हाथ में लेंगे ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है । 10 अगस्त को मैंने मीटिंग बुलाई थी । उसमें राजस्थान के इर्रीगेशन मिनिस्टर आए हुए थे और वे बतला रहे थे कि अपने यहां की नदियों पर तटबन्दी का काम उन्होंने किया हुआ है । इसलिए उनका ख्याल था कि पानी कम आएगा क्योंकि तटबन्दी कर लेने से पानी कनजर्व हो जाएगा ।

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: How many cusecs of water Goverdhan Drain has the capacity to take away from the States? How much is being released actually and whether it is causing flood in the inter-mediate area of Agra District?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह गोवरधन ड्रेन जहां पर खत्म होता है वहां पर दो हजार से ऊपर इसकी कैपेसिटी है । जैसा मैंने अर्ज किया है कि इसमें हरियाणा का पानी जाता है और राजस्थान का पानी जाता है । दोनों स्टेट्स का पानी मिल कर के एक हजार क्यूसेक हो जाता है और कुछ पानी इसमें यू० पी० का भी आता है । इस तरह से दो हजार से ऊपर इसकी कैपेसिटी हो जाती है जबकि यह जमुना में जाकर गिरती है। पिछली दफा ज्यादा पानी होने की वजह से इस से फ्लडिंग हुई जिससे मथुरा और शायद आगरा के एरिये में भी पानी पहुंचा ।

श्री राम किशन : गोवरधन ड्रेन के बारे में माननीय मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं वह गलत है । उन्होंने कहा है कि इस में राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पानी मिलता है । इसमें हरियाणा का पानी भी मिलता है ।

असल में मूल प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि कामा पहाड़ी ड्रेन जो हरियाणा के पानी को ले जाता है और उत्तर प्रदेश के पानी को ले जाता है, उसमें दो रेगुलेटर हैं । एक हरियाणा के कब्जे में है और दूसरा उत्तर प्रदेश के कब्जे में है । जब हरियाणा पानी छोड़ता है और उत्तर प्रदेश पानी लेता नहीं है तो भरतपुर जिला जो कि राजस्थान का जिला है, डूबा रहता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले ले । यदि हां, तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि केन्द्रीय सरकार को उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेने में क्या दिक्कत है ।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह हिस्ट्री बताती है कि राजस्थान ने कई बार राजस्थान में 204 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज की योजना को सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को भेजा है और सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने राजस्थान के लिए जितने पानी की मिकदार रखी है वह उसे नहीं मिलता है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश चूंकि रेगुलेटर उनके हाथ में रहते हैं, इसलिए वे अपनी मिकदार से ज्यादा पानी ले रहे हैं। इन दोनों मामलों के बारे में मंत्री जी स्पष्ट जानकारी दें कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक इनके रेगुलेटर्स अपने हाथ में लेने की बात है, उसके बारे में मीटिंग हुई है और उसमें यह बात डिस्कस हुई है । लेकिन इसके लिए प्रान्तीय सरकारें नहीं मानती हैं । वे कहती हैं कि रेगुलेट हम करेंगे, आप वहां बैठ कर मानिटरिंग कर सकते हैं । यू० पी० के एक मिनिस्टर आये थे । उन्होंने भी यही कहा कि आप मानिटरिंग कर लीजिए, आप बैठ कर वहां देख लीजिए, लेकिन आप आपने हाथ में कंट्रोल नहीं ले सकेंगे । यह उनका ख्याल था । मैं यह बता रहा था कि इसमें हरियाणा का पानी भी आता है । यह तीन स्टेट्स का ड्रेन है । यह झीना से शुरू होता है और फिर यह पहाड़ी कामा ड्रेन बन जाता है इस तरह से तीनों स्टेट्स में जाकर इसका नाम झीना पहाड़ी कामा, गोवरधन ड्रेन हो जाता है । इस तरह से यह ड्रेन तीन स्टेट्स का हो जाता है और इस तरह से इस में तकलीफ आती है ।